

मिशन इंद्रधनुष और सघन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई)

सिलेबस: जीएस पेपर-II (स्वास्थ्य, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)

भारत में उन बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई है जो बिना टीकाकरण के थे या **डिप्थीरिया-टेटनस-पर्टुसिस (डीटीपी)** संयुक्त टीके की अपनी पहली खुराक से चूक गए थे, जैसा कि डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है।

पृष्ठभूमि

- भारत में प्रतिरक्षण कार्यक्रम को 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम (ईपीआई)' के रूप में पेश किया गया था।
- वर्ष 1985 में इस कार्यक्रम को सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) के रूप में संशोधित किया गया था। यूआईपी बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर और रुग्णता को 12 वैक्सीन-रोके जाने योग्य बीमारियों के खिलाफ रोकता है।
- लेकिन अतीत में, यह देखा गया था कि टीकाकरण कवरेज में वृद्धि धीमी हो गई थी और यह 2009 और 2013 के बीच प्रति वर्ष 1% की दर से बढ़ी थी।
- कवरेज में तेजी लाने के लिए, मिशन इंद्रधनुष की परिकल्पना की गई थी और 2015 से लागू किया गया था ताकि पूर्ण टीकाकरण कवरेज को तेजी से 90% तक बढ़ाया जा सके।

मिशन इंद्रधनुष के बारे में

- यह 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें यूआईपी के तहत या तो टीका नहीं लगाया गया है या आंशिक रूप से टीका लगाया गया है।
- यह 12 वैक्सीन-रोकथाम योग्य रोगों (वीपीडी) यानी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, मेनिन्जाइटिस और निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण, जापानी इंसेफलाइटिस (जेई), रोटोवायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल संयुग्म वैक्सीन (पीसीवी) और खसरा-रूबेला (एमआर) के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करता है।
- तथापि, देश के चुनिंदा जिलों में जापानी इंसेफलाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के विरुद्ध टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है।
- मिशन इंद्रधनुषसुह को ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रमुख योजनाओं में से एक के रूप में भी पहचाना गया था।

सघन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) के बारे में

- सघन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) केंद्र सरकार द्वारा 2017 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य दो साल से कम उम्र के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए कवर करना था, जिन्हें यूआईपी के तहत कवर नहीं किया गया था।
- इसने चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके।
- आईएमआई 2.0 पल्स पोलियो कार्यक्रम (2019-20) के 25 वर्षों को चिह्नित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था। इसमें 27 राज्यों में फैले 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य था। इसका उद्देश्य 2022 तक कम से कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना है।
- आईएमआई 3.0 को 2021 में लॉन्च किया गया था। आईएमआई 3.0 का फोकस उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर था, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी वैक्सीन की खुराक गंवा दी थी।
- आईएमआई 4.0 को फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियमित टीकाकरण (आरआई) सेवाएं बिना टीकाकरण वाले और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंच सकें। इस अभियान में दो साल तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा।

भारत विशिष्ट प्रेक्षण

बिना टीकाकरण वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि

- भारत में उन बच्चों की संख्या जो या तो बिना टीकाकरण के थे या डिप्थीरिया-टेटनस-पर्तुसिस (डीटीपी) संयुक्त वैक्सीन की अपनी पहली खुराक से चूक गए थे, **2019 में 1.4 मिलियन से दोगुना होकर 2021 में 2.7 मिलियन हो गए।**
- यह पहली बार है जब पूरे भारत के लिए प्रतिरक्षण में मूल्यांकन कवरेज में गिरावट आई है।

भारत 2020 और 2021 के बीच गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने में सक्षम था

- हालांकि टीकाकरण कवरेज में दुनिया भर में गिरावट जारी है, भारत 2020 और 2021 के बीच प्रवृत्ति को रोकने में सक्षम था।
- शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या 2020 में तेजी से बढ़कर 3 मिलियन हो गई।
- आईएमआई 3.0 जैसे कार्यक्रमों को पकड़ने के कारण एक और बैकस्लाइडिंग को रोका गया था।

ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम

सिलेबस: जीएस पेपर-II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)

केंद्र सरकार ने बिजली (ग्रीन ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम 2022 को अधिसूचित किया है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में तेजी लाएगा।

मुख्य बिंदु

- ग्रीन ओपन एक्सेस की अनुमति किसी भी उपभोक्ता को दी जाती है और **ग्रीन एनर्जी के लिए ओपन एक्सेस ट्रांजैक्शन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है**, ताकि छोटे उपभोक्ता भी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय बिजली खरीद सकें।
- ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले ओपन एक्सेस चार्जेज पर निश्चितता प्रदान करें जिसमें ट्रांसमिशन चार्ज, व्हीलिंग चार्जेज, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और स्टैंडबाय चार्ज शामिल हैं। क्रॉस-सब्सिडी अधिभार को बढ़ाने के साथ-साथ अतिरिक्त अधिभार को हटाने की सीमा, न केवल उपभोक्ताओं को हरे रंग में जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि उन मुद्दों को भी संबोधित करती है जिन्होंने भारत में खुली पहुंच के विकास में बाधा डाली है।
- ओपन एक्सेस एप्लिकेशन की अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता। 15 दिनों में दी जाने वाली मंजूरी अन्यथा इसे तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन अनुमोदित माना जाएगा। यह एक राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से होगा।
- **हरित प्रशुल्क का निर्धारण** हरित ऊर्जा के लिए प्रशुल्क का निर्धारण उपयुक्त आयोग द्वारा अलग से किया जाएगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत पूंछ विद्युत खरीद लागत, यदि कोई हो, तो क्रॉस-सब्सिडी प्रभार, और उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए वितरण लाइसेंसधारक की विवेकपूर्ण लागत को कवर करने वाले सेवा प्रभार शामिल होंगे।
- इन नियमों से नवीकरणीय विद्युत उत्पादकों के लिए नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी में सुधार करने के लिए समय पर अनुमोदन सहित ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए समग्र अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। यह आवेदन प्रक्रिया में एकरूपता भी लाएगा।
- वितरण लाइसेंसधारक के अधिदेशित होने के साथ अधिशेष हरित ऊर्जा की बैंकिंग।
- **वितरण लाइसेंसधारकों के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं पर एक समान नवीकरणीय खरीद दायित्व** होगा। इसने अपने आरपीओ की पूर्ति के लिए ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया को भी शामिल किया है।
- ग्रीन पावर की खपत करने पर उपभोक्ताओं को **ग्रीन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे**।
- यदि हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

अर्थ

- इन नियमों को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है।
- अधिसूचित नियम हरित शक्ति तक खुली पहुंच के लिए सरलीकृत प्रक्रिया को सक्षम करते हैं। इससे ग्रीन ओए, यूनिफॉर्म बैंकिंग, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा आरई पावर की स्वैच्छिक खरीद, ओए शुल्क की प्रयोज्यता आदि को तेजी से मंजूरी मिल सकेगी।
- यह सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।
- यह 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन पर 500 गीगावॉट की भारत की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने में मदद करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा मुख्य तथ्य

पार्टिसिपेटरी नोट्स

- पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के माध्यम से भारतीय पूंजी बाजार में निवेश घटकर 80,092 करोड़ रुपये रह गया, जो इसे 20 महीनों में सबसे निचला स्तर बनाता है।
- पार्टिसिपेटरी नोट्स उन विदेशी निवेशकों के लिए पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) द्वारा जारी किए गए उपकरण हैं जो सेबी के तहत पंजीकृत हुए बिना भारत के शेयर बाजारों में निवेश करना चाहते हैं।
- पी-नोट्स अंतर्निहित संपत्ति के रूप में इक्विटी शेयरों या ऋण प्रतिभूतियों के साथ अपतटीय व्युत्पन्न निवेश (ओडीआई) हैं।
- वे निवेशकों को तरलता प्रदान करते हैं क्योंकि वे समर्थन और वितरण द्वारा स्वामित्व को स्थानांतरित कर सकते हैं।
- जबकि एफआईआई को प्रत्येक तिमाही में सेबी को ऐसे सभी निवेशों की रिपोर्ट करनी होती है, उन्हें वास्तविक निवेशकों की पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में दूध उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए स्वदेशी गोजातीय नस्लों को विकसित करने और संरक्षित करने की पहल के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें बेहतर पोषण और कृषि प्रबंधन शामिल है।
- इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
 1. स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना।
 2. आनुवंशिक मेकअप में सुधार के लिए एक नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू करने के लिए।
 3. दूध उत्पादन और उत्पादकता में सुधार और वृद्धि करने के लिए।
 4. गिर, साहीवाल, राठी, देवनी, थारपारकर, लाल सिंधी जैसी कुलीन देशी नस्लों का उपयोग नॉनडेस्क्रिप्ट मवेशियों के उन्नयन के लिए किया जाता है।
 5. प्राकृतिक सेवा के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक योग्यता बैल वितरित करने के लिए।

सूराख

- एक वर्महोल एक अंतर-गैलेक्टिक संरचना है जो अंतरिक्ष-समय में दूर के बिंदुओं को जोड़ती है। इसे Einstein Rosen Bridge भी कहा जाता है।
- 1957 में, भौतिक विज्ञानी जॉन आर्किबाल्ड व्हीलर ने "वर्महोल" नाम पेश किया।
- भौतिक विज्ञानी लुडविग फ्लैम सामान्य सापेक्षता के समीकरणों के कुछ समाधानों का विश्लेषण करते हुए वर्महोल के विचार के साथ आए थे।
- हालांकि, आज तक कोई वर्महोल नहीं खोजा गया है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि (NCF)

- एनसीएफ की स्थापना धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 के तहत ट्रस्ट के रूप में की गई थी, जो भारत में कला और संस्कृति के लिए मौजूदा स्रोतों और वित्तपोषण के पैटर्न से अलग फंडिंग तंत्र के रूप में थी।
- यह केंद्रीय संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है और नीतियों का निर्णय लेता है।
- इसकी कार्यकारी समिति की अध्यक्षता संस्कृति मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है जो उन नीतियों को वास्तविक बनाती है।
- राष्ट्रीय संस्कृति कोष (NCF) का उद्देश्य-
 1. निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों, सरकारी, गैर-सरकारी एजेंसियों, निजी संस्थानों और नींव के साथ संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में साझेदारी स्थापित करना और पोषण करना।
 2. भारत की समृद्ध, प्राकृतिक, मूर्त और अमूर्त विरासत के जीर्णोद्धार, संरक्षण, संरक्षण और विकास के लिए संसाधन जुटाना।

भील जनजाति

- भील छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहने वाले सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है।
- यह नाम 'बिल्लू' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है धनुष।
- भील को अपने स्थानीय भूगोल के बारे में गहरे ज्ञान के साथ मिलकर उत्कृष्ट तीरंदाजों के रूप में जाना जाता है।
- परंपरागत रूप से, गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ, उनमें से अधिकांश आज किसान और खेतिहर मजदूर हैं। वे कुशल मूर्तिकार भी हैं।
- **1818 का भील विद्रोह**, देश में एक आदिवासी समूह द्वारा किए गए पहले विद्रोहों में से एक है। विद्रोह का कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों भीलों के साथ क्रूर व्यवहार था, जिन्होंने उन्हें अपने पारंपरिक वन अधिकारों से वंचित कर दिया और उनका शोषण किया।